भारत-यूके सीटीए 15 जुलाई से लागू

99% भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन में आयात शुल्क समाप्त, निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

नई दिल्ली, 18 जून भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने जा रहा है. इसके साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

समझौते के तहत ब्रिटेन भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को व्यापक रूप से खोलेगा और 99 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर देगा. वहीं, ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा योगदान के दोहरे भुगतान से पांच वर्षों तक छूट मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत-यूके संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति देगा तथा किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों के लिए नए अवसर पैदा करेगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

> समझौते का एक प्रमुख आकर्षण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी राहत है. नए प्रावधानों के तहत ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योगदान के दोहरे भुगतान से पांच वर्षों तक छूट मिलेगी, जबकि पहले यह अवधि केवल तीन वर्ष थी. सरकार के अनुसार, इस कदम से लगभग 75,000 भारतीय पेशेवरों और 900 भारतीय कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. इसके अलावा हर वर्ष 1,800 भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षकों और शास्त्रीय संगीत कलाकारों के लिए ब्रिटेन में विशेष कार्य अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

सोना-चांदी में भारी गिरावट दर्ज

चांदी 3,988 टूटी, सोना 816 सस्ता हुआ

नई दिल्ली, 18 जून देश में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और आभूषण बाजार में हलचल देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है.

चांदी के भाव में एक ही दिन में 3,988 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर लगभग 2.44 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. इससे पहले चांदी करीब 2.48 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी. यह गिरावट चांदी को उसके ऑलटाइम हाई से काफी नीचे ले आई है. आंकड़ों के अनुसार चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अब तक लगभग 1.42 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है.

इसी तरह सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 816 रुपये गिरकर लगभग 1.49 लाख रुपये पर आ गया है. यह गिरावट सोने को भी उसके पिछले उच्च स्तर से नीचे ले आई है.

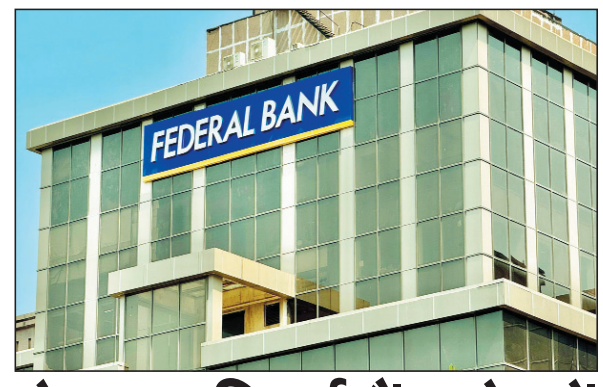

फेडरल रिजर्व बैंक ने दरें की स्थिर, वृद्धि घटाई

अमेरिकी जीडीपी वृद्धि अनुमान 2.4 से घटाकर 2.2 प्रतिशत किया.

महंगाई अनुमान बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत किया, कीमतों पर चिंता

वॉशिंगटन, 18 जून अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई को लेकर जारी चिंताओं के बीच अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. दो दिवसीय बैठक के बाद फेड की मुक्त बाजार समिति (एफओएमसी) ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने का निर्णय लिया.

इसके साथ ही फेड ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए वर्ष 2026 के लिए अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान में कटौती कर दी है.

बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक का नेतृत्व करने वाले केविन वार्श ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखना उचित माना गया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय फेडरल रिजर्व की दोहरी जिम्मेदारी—मूल्य स्थिरता बनाए रखने और अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करने—के अनुरूप है. उन्होंने यह भी दोहराया कि केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त रिजर्व बनाए रखने की अपनी नीति पर कायम रहेगा.

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के सभी 12 सदस्यों ने दरों को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया. इससे यह संकेत मिलता है कि नीति निर्धारकों के बीच वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर व्यापक सहमति है. समिति द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और ऊर्जा क्षेत्र में लागत बढ़ने के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है.

> फेड का यह फैसला संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है. दरों को स्थिर रखते हुए उसने एक ओर आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने का प्रयास किया है, वहीं महंगाई को लेकर अपनी सतर्कता भी स्पष्ट कर दी है. आने वाले महीनों में महंगाई, रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों के रुख के आधार पर फेड की अगली नीतिगत दिशा तय होगी.

इंडिगो ने शुरू की 'कैब्स विद इंडिगो' सेवा

नयी दिल्ली, 18 जून निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने गुरुवार को 'कैब्स विद इंडिगो' सेवा शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत यात्रियों को हवाई अड्डों तक पहुंचने या हवाई अड्डे से आगे की अपनी यात्रा के लिए चिंता से मुक्ति मिल जायेगी.

इंडिगो ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह विशेष एयरपोर्ट ट्रांसफर सेवा देश के सभी शहरों में उन हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी जहां इंडिगो की उड़ान है. इस सेवा को इंडिगो के लॉयल्टी प्रोग्राम 'इंडिगो ब्लूचिप' के साथ एकीकृत किया गया है. इसके माध्यम से सदस्य 'कैब्स विद इंडिगो' पर खर्च किये गये प्रत्येक 100 रुपये पर पांच इंडिगो ब्लूचिप्स अर्जित कर सकते हैं. इससे यात्रियों को अधिक रिवॉर्ड्स और तेजी से पॉइंट्स जमा करने का लाभ मिलेगा.

कहा गया है कि इंडिगो लगातार ग्राहकों की यात्रा को शुरू से अंत तक आसान बनाने के उद्देश्य से एक समग्र यात्रा पारितंत्र विकसित कर रही है. हवाई यात्रा के अलावा इंडिगो सात लाख से अधिक होटलों के विकल्पों और चुनिंदा दर्शनीय स्थलों के लिए बुकिंग की सुविधा भी प्रदान करती है. इसी दिशा में 'कैब्स विद इंडिगो' एक स्वाभाविक विस्तार है. मोजोबॉक्स द्वारा संचालित 'कैब्स विद इंडिगो' यात्रियों को एक भरोसेमंद और पारदर्शी परिवहन समाधान प्रदान करती है.

वैज्ञानिक खदान बंदी से विकास की राह आसान

नागपुर, 18 जून कोयला खनन राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला है, लेकिन एक जिम्मेदार खनन कंपनी की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने खनन कार्य की समाप्ति के बाद प्रकृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार करती है.

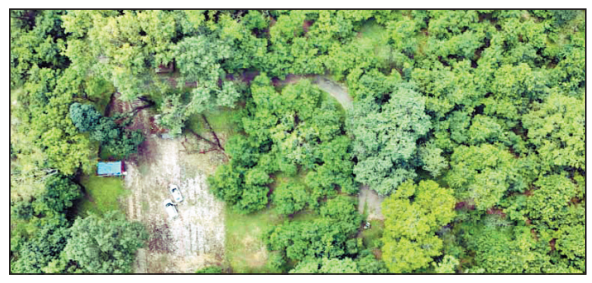

इसी सोच को व्यवहार में उतारते हुए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) ने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खदान बंदी के क्षेत्र में पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है. भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए उसके संचालन काल में ही अंतिम खदान बंदी की विस्तृत योजना तैयार की जाती है. इसका उद्देश्य केवल खनन गतिविधियों को समाप्त करना नहीं, बल्कि भूमि का पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है. वेकोलि ने इन सभी प्रावधानों का अक्षरश: पालन करते हुए खदान बंदी को अपनी सतत विकास नीति का अभिन्न अंग बनाया है. वेकोलि को यह गौरव प्राप्त है किकोल इंडिया लिमिटेड की पहली व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से बंद की गई खदानइसी कंपनी की थी. यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि वेकोलि ने समय रहते यह समझ लिया था कि आधुनिक खनन केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके उपयोग के बाद प्रकृति को सुरक्षित और संतुलित स्वरूप में लौटाना भी उतना ही आवश्यक है.

इसी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप आज तक वेकोलि कीपाथाखेड़ा-I भूमिगत, पाथाखेड़ा-II भूमिगत, सतपुड़ा-ढ्ढ भूमिगत, न्यू माजरी-III भूमिगत, अदासा भूमिगत, पिपला भूमिगत, झरना भूमिगत, अंबारा भूमिगत तथा गणपति भूमिगत खदानोंको कोयला मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से बंद किया जा चुका है.

> वेकोलि की व्यवस्थित खदान बंदी का लाभ केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है. इससे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी अधिक सुरक्षित और बेहतर बना है. परित्यक्त खदानों से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त हुई है, भूमि अधिक सुरक्षित बनी है तथा स्थानीय क्षेत्र में स्वच्छ और हरित वातावरण का विकास हुआ है. पुनर्स्थापित भूमि भविष्य में विभिन्न सामुदायिक एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है. इस प्रकार खान बंदी स्थानीय समाज के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है.

23 जून को खुला आईपीओ बैंड रुपए 130-138

मुंबई, 15 जून 2026: अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड ने अपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड 130 रुपये से 138 रुपये तय कर दिया है.

> अद्वित ज्वेल्स भारत में रत्नों और गहनों के सबसे बड़े गढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित है. यह कंपनी पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह के हाथ से बने बेहतरीन गहने बनाने और बेचने का काम करती है.

कंपनी का यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ('आईपीओ' या 'इश्यू') सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार, 23 जून 2026 को खुलेगा और गुरुवार, 25 जून 2026 को बंद हो जाएगा.

इन्वेस्टर कम से कम 100 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, और उसके बाद 100 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल्स में ही दांव लगा पाएंगे.

आज की तारीख में कंपनी के कुल 3,38,42,000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग हैं, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है.

इस आईपीओ के तहत 1,19,68,000 इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू (नए शेयर) जारी किए जा रहा है.इस फ्रेश इश्यू से मिलने वाले पैसों में से 65 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल (रोजमर्रा के कामकाज के खर्च) की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. वहीं, 65 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी पर बकाया कुछ कर्जों को पूरा या आंशिक चुकाने के लिए होगा. बाकी बची रकम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (जनरल कॉर्पोरेट पर्पज) पर खर्च की जाएगी.

एनएसई आईपीओ से एसबीआई को बड़ा लाभ

नई दिल्ली, 18 जून देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के संभावित आईपीओ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सहित कई संस्थानों को भारी वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है. करीब 30 साल पहले किए गए छोटे निवेश अब हजारों करोड़ रुपये के मूल्य में बदलते दिखाई दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, एसबीआई ने एनएसई में शुरुआती दौर में लगभग 1.98 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिससे उसने बड़ी संख्या में शेयर हासिल किए थे.

शेयर बाजारों में लगातार पांचवें दिन तेजी

254 अंक चढ़ा सेंसेक्स

82.30 अंक पर आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 18 जून अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की मुख्य बातें सामने आने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन तेजी देखी गयी.

अमेरिका ने ईरान के साथ सहमति पत्र की मुख्य बातें सार्वजनिक की हैं. इसमें 60 दिन के भीतर प्रस्तावित अंतिम समझौते से पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने की बात भी शामिल है. इससे निवेशकों में उत्साह दिखा.

बीएसई का सेंसेक्स 254.36 अंक (0.33 प्रतिशत) चढ़कर कारोबार की समाप्ति पर 77,409.98 अंक पर पहुंच गया. यह 07 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 82.30 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,168 अंक पर बंद हुआ. यह 08 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है.

वृहत बाजार में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.32 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.44 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. आईटी सेक्टर दबाव में रहा. निफ्टी आईटी सूचकांक 1.19 प्रतिशत टूट गया.

समाचार विशेष

राजनीति में जातीय समीकरणों की नई जंग

चंडीगढ़. पंजाब में 2026-27 चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने जाति आधारित राजनीति को तेज कर दिया है. आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी), बीजेपी और कांग्रेस चारों ही अलग-अलग समुदायों को साधने में जुट गए हैं.

ये चारों पार्टियां अपने पारंपरिक जनाधार को बचाने के साथ-साथ एक जातीय समीकरण बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं. इन पार्टियों की नजर जाट सिख, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां के अलावा व्यापारी, महिला और युवा वर्ग पर है. पंजाब की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है, जबकि हिंदू लगभग 38 प्रतिशत हैं. दशकों तक पंजाब में बीजेपी को मुख्य रूप से शहरी हिंदू वोटरों का ही समर्थन मिलता रहा है. हाल ही में बीजेपी ने सिख जाट नेता केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का राज्याध्यक्ष बनाया है. बीजेपी का यह कदम पंजाब में उसकी हिंदू पार्टी वाली छवि को बदलने और सिख वोटरों, खासकर प्रभावशाली जाट सिख समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के तौर पर देख जा रहा है. इसके अलावा बीजेपी

ओबीसी, सैनी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बीच लगातार कोई न कोई कार्यक्रम या संवाद के जरिए पैठ बनाने का प्रयास कर रही है.

ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की नजर रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण पंजाब के मालवा, दोआबा और माझा पर है. केवल सिंह ढिल्लों मालवा इलाके से आते हैं, जहां पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें हैं. माझा इलाके में 25 सीटें, जबकि दोआबा में 23

अकाली दल सत्ता की क्या है रणनीति

पंजाब की राजनीति पारंपरिक रूप से जाट सिख प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूमती रही है. अकाली दल का मुख्य समर्थन आधार प्रदेश में जाट सिख, पंथ सिख रहा है. वहीं, कांग्रेस का समर्थन आधार जाट सिख, दलित और कुछ हिंदुओं का समर्थन रहा है. साल 2022 में आप के सत्ता में आने के बाद से इन पार्टियों के समर्थन आधार में सेंध लगी है. अकाली दल एक बार फिर से अपना पारंपरिक वोट वापस पाने में लगी है. हालांकि, एसएडी अपने वोट आधार से हटकर पहले 70 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में एससी-बीसी, महिला और युथ विंग को सक्रिय कर चुकी है. इसके अलावा एसएडी ने 67 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापार विंग के 67 विभिन्न विधानसभा हलकों के हलका प्रधानों की नियुक्ति की है.

दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर 'सुप्रीम' संकट

कोर्ट ने बिहार सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

पटना. राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा बढ़ा गया है. बिना विधायक या विधान परिषद के सदस्य बने दीपक के दोबारा मंत्री बन गए. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. दोबारा मंत्री बनने पर याचिका के जरिए चुनौती देते हुए मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी. ष्टछ्ढ सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने भी इस याचिका पर दीपक प्रकाश से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस बिहार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति और पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा गया है, जबकि वे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के. बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का तर्क है कि प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, और अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-विधायकों को मंत्री बने रहने के लिए मिलने वाली छह महीने की छूट का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता है.

अधिकतम 6 महीने बन सकते हैं मंत्री

बता दें, बिना किसी सदन के सदस्य रहे कोई नेता एक बार अधिकतम छह महीने तक ही मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है. वहीं, दीपक प्रकाश पहले नीतीश कुमार की सरकार में 5 महीने तक मंत्री रहे उसके बाद अब सम्राट चौधरी की सरकार में फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली. इस दौरान वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए.

केसीआर का दांव आजमाएंगे केजरीवाल

नई दिल्ली. ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल चौंकाने वाला कोई फैसला कर सकते हैं. जानकार सूत्रों का कहना है कि वे पंजाब में समय से पहले चुनाव करा सकते हैं.

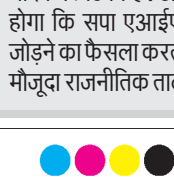

ध्यान रहे पंजाब में अगले साल मार्च में चुनाव होने वाला है. बताया जा रहा है कि केजरीवाल उससे पहले नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं. अगर ऐसा है तो उनको अभी तुरंत विधानसभा भंग करानी होगी. केजरीवाल ने इसकी शुरुआत करा दी है. उन्होंने अचानक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अगले चुनाव के लिए पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया. अभी सीएम फेस घोषित करने की जरुरत नहीं थी. तभी यह चर्चा शुरू हुई कि अब विधानसभा भंग करने की सिफारिश भगवंत मान कर सकते हैं. ध्यान रहे अगर अभी विधानसभा भंग होती है तभी छह महीने के भीतर यानी नवंबर या दिसंबर तक चुनाव होगा. अगर इसमें देरी होगी तो फिर मामला चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा.

विशेष | क्या साथ आएंगे अखिलेश?

ओवैसी ने सपा से गठबंधन का बढ़ाया हाथ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं. इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन की इच्छा जताकर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. बहराइच दौरे के दौरान ओवैसी ने कहा कि यदि कोई भाजपा को रोकने का प्रयास करता है तो वह उसके साथ आने को तैयार हैं.

ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरणों पर विचार कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिला था, जिससे विपक्ष को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई थी. हालांकि, उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अब तक कोई बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं छोड़ पाई है. 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. वहीं 2022 चुनाव में करीब 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद पार्टी का वोट शेयर 0.43 प्रतिशत ही रहा. हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

ओवैसी के प्रस्ताव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा को हराने वाला कोई भी प्रयास स्वागत योग्य है. लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही लेना होगा. विश्लेषकों के अनुसार एआईएमआईएम को साथ लेने से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना कम हो सकती है, लेकिन इससे भाजपा को ध्रुवीकरण का मुद्दा भी मिल सकता है. सपा फिलहाल अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को मजबूत करने पर जोर दे रही है और नहीं चाहती कि चुनाव का केंद्र धार्मिक ध्रुवीकरण बने.

मुस्लिम वोट बैंक पर सपा की मजबूत पकड़-

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है और 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर यह समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में है. सपा लंबे समय से मुस्लिम-यादव समीकरण को अपनी राजनीतिक ताकत मानती रही है. ऐसे में पार्टी के भीतर यह धारणा है कि मुस्लिम मतदाता भाजपा को हराने की क्षमता रखने वाले दल के साथ जाएंगे और वर्तमान में सपा इस भूमिका में सबसे मजबूत विपक्षी विकल्प है.

पिछले गठबंधनों से भी सीख ले रही सपा

सपा नेतृत्व छोटे दलों के साथ गठबंधन को लेकर सतर्क दिखाई देता है. पार्टी के भीतर राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा जैसे पुराने गठबंधनों का उदाहरण दिया जाता है, जो समय-समय पर राजनीतिक पाला बदलते रहे हैं. यही वजह है कि सपा संगठनात्मक मजबूती और अपने सामाजिक समीकरणों के दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हैं. आने वाले समय में यह साफ होगा कि सपा एआईएमआईएम को अपने साथ जोड़ने का फैसला करती है या फिर कांग्रेस के साथ मौजूदा राजनीतिक तालमेल को ही आगे बढ़ाती है.